17 प्रतिशत ई-कुकिंग के साथ दिल्ली और तमिलनाडु इलेक्ट्रिक कुकिंग को अपनाने में भारत का नेतृत्व करते हैं: सीईईडब्ल्यू

- 10 प्रतिशत शहरी परिवार पहले ही ई-कुकिंग को अपना चुके हैं

- घरेलू बिजली पर ज्यादा सब्सिडी वाले राज्य ई-कुकिंग को अपनाने में तेजी देखेंगे

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2021: दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और केरल ने इंडक्शन कुकटॉप (चूल्हा), राइस कुकर, और माइक्रोवेव ओवेन जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग (ई-कुकिंग) उपकरणों को अपनाने में क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की है। यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा आज जारी एक स्वतंत्र अध्ययन में दी गई है। दिल्ली और तमिलनाडु में, 17 प्रतिशत परिवारों ने अलग-अलग तरह से इलेक्ट्रिक कुकिंग को अपनाया है, जबकि तमिलनाडु में इसे अपनाने की दर 15 प्रतिशत है। केरल और असम में, 12 प्रतिशत परिवारों ने आंशिक रूप से ई-कुकिंग को अपनाया है। इस साल फरवरी में, भारत सरकार ने बिजली उपकरणों से खाना पकाने के लाभों को प्रोत्साहित करने के लिए *गो इलेक्ट्रिक* अभियान शुरू किया था।

सीईईडब्ल्यू का अध्ययन बताता है कि ई-कुकिंग का शहरी इलाकों में विस्तार 10.3 प्रतिशत, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 2.7 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर, देश में कुल पांच प्रतिशत परिवारों ने ही ई-कुकिंग को अपनाया है। एलपीजी की मौजूदा कीमत पर, सब्सिडी आधारित बिजली पाने वाले परिवारों के लिए ई-कुकिंग एलपीजी की तुलना में कम खर्चीली पड़ेगी। हालांकि, इस पर शुरुआत में आने वाली शुरुआती लागत और धारणाओं से जुड़ी बाधाओं के कारण शहरी परिवारों के बीच ई-कुकिंग को अपनाने की दर सीमित है।

सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में यह भी पाया गया है कि ई-कुकिंग को अपनाने वाले 93 प्रतिशत परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन के रूप में एलपीजी पर निर्भर हैं और ई-कुकिंग उपकरणों को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के संपन्न परिवारों में बिजली के उपकरणों की मदद से खाना पकाने का प्रचलन ज्यादा है। खास तौर पर, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका ज्यादा चलन है, जहां पर महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों की तुलना में बिजली सस्ती है।

सीईईडब्ल्यू का यह अध्ययन 'इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे (आईआरईएस) 2020' पर आधारित है, जो इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी (आईएसईपी) के साथ साझेदारी में किया गया था। यह निष्कर्ष सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 21 राज्यों के 152 जिलों में लगभग 15 हजार शहरी और ग्रामीण परिवारों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।

शालू अग्रवाल, लेखक और सीनियर प्रोग्राम लीड, सीईईडब्ल्यू, ने कहा, "खाना पकाने वाले किसी ईंधन का किफायती होना सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यही उसके इस्तेमाल की दर तय करता है। इसलिए, बिजली पर ज्यादा सब्सिडी देने वाले राज्यों में संपन्न परिवारों के बीच ई-कुकिंग तेजी से प्रचलित होने की संभावना है। इस बदलाव के लिए सरकार को ई-कुकिंग उपकरणों पर आने वाले शुरुआती खर्च को घटाने और सस्ती दर पर बिजली की भरोसमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता वाली विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) वित्तीय संस्थाओं के साथ भी साझेदारी कर सकती हैं, ताकि ई-कुकिंग को अपनाने के इच्छुक उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक उपकरणों को खरीदने के लिए सस्ते कर्ज के विकल्प दिए जा सकें।"

डॉ. अरुणाभा घोष, सीईओ, सीईईडब्ल्यू, ने कहा, "आने वाले दशकों में ई-कुकिंग को अपनाने में मिली सफलता ऊर्जा से जुड़े बदलावों का नेतृत्व करने की भारत के सामर्थ्य का एक और उदाहरण होगी। भारत ने घरेलू प्रदूषण को घटाने में लगातार प्रगति की है। अभी 85 प्रतिशत परिवारों के पास एलपीजी सिलेंडर के रूप स्वच्छ ईंधन तक पहुंच है। चूंकि शहरी परिवारों के बीच इलेक्ट्रिक कुकिंग

को अपनाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इस बदलाव में मदद करने से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की बचत होगी।"

सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि ई-कुकिंक को बढ़ावा देने में खाना पकाने वाले कुशल और कम लागत वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों, उपयुक्त वित्तीय समाधानों और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी (बीईई) को राइस कुकर और इंडक्शन चूल्हे जैसे ई-कुकिंग उपकरणों को अपने मानक और लेबलिंग कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इतना ही नहीं, देश भर में इलेक्ट्रिक कुकिंग को अपनाने से बिजली की 243 टेरावाट-घंटे (टीडब्ल्यूएच) अतिरिक्त मांग पैदा होगी। इसलिए, इस अतिरिक्त मांग को स्वच्छ संसाधनों के माध्यम से पूरा करने की प्राथमिकता होनी चाहिए।

अध्ययन 'आर इंडियन होम्स रेडी फॉर इलेक्ट्रिक कुकिंग' को यहां पर देखा जा सकता है।

संपर्क: रिद्धिमा सेठी (सीईईडब्ल्यू) - riddhima.sethi@ceew.in; / mihir.shah@ceew.in

सीईईडब्ल्यू के बारे में

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू), एशिया के अग्रणी गैर-लाभकारी नीति शोध संस्थानों में से एक है। काउंसिल संसाधनों के उपयोग, पुन: उपयोग, और दुरुपयोग की व्याख्या करने- और बदलाव लाने- के लिए आंकड़े, समेकित विश्लेषण, और रणनीतिक संपर्क का उपयोग करती है। यह अपने उच्च गुणवत्ता वाले शोध की स्वतंत्रता के लिए स्वयं पर गर्व करती है, सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित करती है, और व्यापक जनता के साथ जुड़ाव रखती है। 2021 में, सीईईडब्ल्यू को एक बार फिर 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में सभी 10 श्रेणियों में व्यापक रूप से स्थान मिला है। काउंसिल को लगातार दुनिया के जलवायु परिवर्तन संबंधी शीर्ष थिंक टैंक में स्थान दिया गया है। ताजा अपडेट के लिए हमें ट्विटर @CEEWIndia पर फॉलो करें।